भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1163

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ा सूखा

1163. डॉ. के. सुधाकर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा आसन्न है और किसान इसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास चिकबल्लापुर के किसानों को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन प्रेरित सूखे के संबंध में कोई अध्ययन रिपोर्ट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आज की कृषि उपज कल की पीढ़ी के लिए संरक्षित है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार मौसम की चरम घटनाएं हो रही हैं, जिसका प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। वर्षा में बदलाव से चरम मौसम जैसे सूखा और बाढ़ की बार-बार होने वाली बढ़ती घटनाओं के कारण कृषि प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के आसन्न खतरे को देखते हुए, देश भर में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वर्षा सिंचित कृषि को अधिक उत्पादक, सतत, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाना है। कृषि वानिकी उप-मिशन का उद्देश्य खेत के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने के लिए वृक्ष आवरण को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का उद्देश्य खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) को अपनाना और एक्विफायर के रिचार्ज को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान पर पूरी बीमा राशि प्रदान करती है। इसके अलावा, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि जैव विविधता के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (बीपीकेपी) का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसानों में जागरूकता पैदा करना है। समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य भी जलवायु सहिष्णुता को बढ़ाना है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और कृषि में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है, जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करेगी और परियोजना के परिणाम सूखा, बाढ़, पाला, गर्मी की लहरों आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में मदद करेगी । आईसीएआर की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

- पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति सहनशील पाई गई हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्य रूप से 651 कृषि प्रधान जिलों हेतु जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है। कुल 109 जिलों को 'बहुत उच्च' और 201 जिलों को 'अत्यधिक' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएँ (डीएसीपी) मौसम संबंधी असमानताओं जैसे सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और चरम मौसम की घटनाओं जैसे लू, शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि के लिए तैयार की गई हैं और राज्य के कृषि विभागों और किसानों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों और किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की गई है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "जलवायु अनुकूल गांवों" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है।
- किसानों द्वारा अपनाने के लिए जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील 151 जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया।
- आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जलवायु अनुकूल कृषि (सीआरए) प्रौद्योगिकी 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 151 जिलों में 448 सीआरवी में कार्यान्वित की गई है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक का चिकबल्लापुर जिला जलवायु परिवर्तन से प्रभावित माना जाता है। किए गए अध्ययन के अनुसार, प्री-मानसून वर्षा (अप्रैल-मई) बढ़ रही है और शुरुआती खरीफ के दौरान बारिश कम हो रही है। वर्ष 2035 तक जिले में अनुमानित वर्षा में 20-25% की वृद्धि होने की उम्मीद है, तथापि इसके वितरण में स्थानिक और अस्थायी दोनों रूप से बदलाव होगा। जिले में बढ़ते तापमान और घटते भूजल के कारण विभिन्न फसलों के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ रही है।

*****